अमलाई में सरकारी धन की बर्बादी का नायाब नमूना!

पुरानी स्ट्रीट लाइट के बगल में लगा दिए हाईमास्ट खंभे

एक ही स्थान पर दो-दो खंभे, फिर भी रोशनी की व्यवस्था अधूरी

अमृत योजना में क्षतिग्रस्त फुटपाथ और बंद लाइटों की मरम्मत के बजाय नए खंभों पर खर्च को लेकर उठे सवाल



नगर परिषद बरगवां-अमलाई के अंतर्गत अमलाई बापू चौक से बरगवां स्थित हनुमान मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अब नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सडक़ किनारे पहले से लगी लाइटों के बीच आधुनिक डिजाइन के हाईमास्ट खंभे स्थापित किए गए हैं। कई स्थानों पर पुराने और नए खंभे पास-पास दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुरानी प्रकाश व्यवस्था लंबे समय से बंद होने की बात सामने आई है।

अमलाई।

नगर परिषद बरगवां-अमलाई में विकास कार्यों की प्राथमिकता और सरकारी धन के उपयोग को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। बापू चौक से बरगवां स्थित हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगाई गई आधुनिक डिजाइन की लाइटें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उपलब्ध तस्वीरों में सडक़ के दोनों ओर पुराने स्ट्रीट लाइट खंभों के साथ नए खंभे नजर आ रहे हैं। कई जगह दोनों प्रकार के खंभे एक-दूसरे के बेहद नजदीक स्थापित किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुराने खंभे पहले से मौजूद थे, तब उनके रखरखाव और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय नए खंभे लगाने की आवश्यकता का आकलन किस आधार पर किया गया?

पाइपलाइन के काम में क्षतिग्रस्त हुए फुटपाथ

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाली एजेंसी के कार्य के दौरान सडक़ के दोनों ओर फुटपाथ के लिए लगाए गए टाइल ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए थे। आरोप है कि लाखों रुपये की लागत से तैयार किए गए फुटपाथ के ब्लॉक उखाडक़र इधर-उधर फेंक दिए गए और उनकी समुचित बहाली नहीं की गई। इसी दौरान स्ट्रीट लाइट के लिए बिछाई गई भूमिगत केबल भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुरानी प्रकाश व्यवस्था बंद होने की बात कही जा रही है। यदि यह स्थिति एक वर्ष से बनी हुई है, तो संबंधित अधिकारियों की निगरानी और मरम्मत व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

पुरानी व्यवस्था सुधारने के बजाय नए खंभों पर खर्च क्यों?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सडक़ पर पहले से स्ट्रीट लाइट के खंभे मौजूद थे, तो उनकी केबल और विद्युत व्यवस्था की मरम्मत कराकर उन्हें दोबारा चालू कराने की संभावनाओं पर प्राथमिकता से विचार क्यों नहीं किया गया? नई लाइटें लगाने के निर्णय से पहले क्या पुराने खंभों की स्थिति, बिजली आपूर्ति और मरम्मत की लागत का तकनीकी परीक्षण कराया गया था? यदि कराया गया था, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। तस्वीरों में कुछ स्थानों पर पारंपरिक सजावटी लाइटों और सामान्य स्ट्रीट लाइट वाले खंभों की निकटता स्पष्ट दिखाई देती है। इससे कार्य की उपयोगिता और स्थल चयन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, केवल तस्वीरों के आधार पर नए खंभों की तकनीकी आवश्यकता या खर्च में अनियमितता को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन संबंधित निकाय को इन सवालों का जवाब अवश्य देना चाहिए।

कहीं रोशनी की जरूरत, कहीं खंभों की भरमार!

नगर परिषद क्षेत्र में ऐसे स्थानों की ओर भी ध्यान दिलाया जा रहा है, जहां नागरिकों को प्रकाश व्यवस्था की जरूरत है और लोग लंबे समय से लाइट लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यदि सीमित दूरी पर पहले से मौजूद खंभों के आसपास ही नए खंभे लगा दिए जाते हैं, तो विकास कार्यों की प्राथमिकता पर सवाल उठना लाजिमी है। नगर परिषद को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नई लाइटों के लिए स्थानों का चयन किस सर्वेक्षण के आधार पर हुआ और क्या पूरे क्षेत्र की जरूरतों का तुलनात्मक आकलन किया गया था।

सीएमओ, अध्यक्ष और उपयंत्री की जवाबदेही तय हो

इस पूरे मामले में नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष तथा संबंधित उपयंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्यों की उपयोगिता, तकनीकी स्वीकृति, स्थल चयन, लागत निर्धारण और गुणवत्ता की निगरानी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली के दायरे में आती है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि नए खंभे लगाने का प्रस्ताव किसने तैयार किया, किस स्तर पर स्वीकृति दी गई और काम पूरा होने के बाद उसका सत्यापन किस अधिकारी ने किया। यदि पुराने खंभों की केबल क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रकाश व्यवस्था बंद थी, तो उसकी मरम्मत के विकल्प की जांच भी सामने आनी चाहिए। साथ ही, पाइपलाइन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त फुटपाथ की बहाली की जिम्मेदारी किस एजेंसी की थी और इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई, इसका विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

जांच हो, खर्च का हिसाब सार्वजनिक किया जाए

नगर परिषद को इस कार्य की तकनीकी जांच कराकर स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यादेश, भुगतान विवरण और स्थल चयन संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। यदि जांच में अनावश्यक खर्च, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। विकास का उद्देश्य केवल नए खंभे खड़े करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यदि पुरानी लाइटें बंद पड़ी हों, फुटपाथ क्षतिग्रस्त हों और दूसरी ओर नए खंभे लगाने पर राशि खर्च की जाए, तो नगर परिषद की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में स्पष्टीकरण देते हैं या यह व्यवस्था यूं ही सरकारी धन के उपयोग पर सवालों का प्रतीक बनी रहती है।

इनका कहना है...

लाईट जलेगी, वॉटर सप्लाई वाली पाईप लाईन डालने वालों ने पूरी तार टूट गये हैं, उनका काम पूरा हो जाये तो, उसके बाद काम होगा। लाईट का काम 30-40 लाख के आस-पास है, ठेकेदार बाहर का है।

अंजनी प्रजापति
उपयंत्री
नगर परिषद बरगवां-अमलाई

नगर परिषद के निर्माण कार्यों से लेकर स्वास्थ्य और राशन तक के मुद्दे उठाए

शहडोल। जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यौहारी के अध्यक्ष सतेंद्र त्रिपाठी 'पिंटू' के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और नगर परिषद ब्यौहारी के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर शहडोल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आवास योजना, सडक़-नाली निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, अवैध रेत एवं शराब कारोबार सहित कुल 17 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने तथा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 में डामरीकरण सडक़ निर्माण की गुणवत्ता और भुगतान की जांच कराने की मांग की। वार्ड क्रमांक 3 में सीव-शहडोल मार्ग से चौरा तालाब तक नाली निर्माण में पेयजल पाइपलाइन के ऊपर नाली बनाए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही नगर परिषद में पिछले चार वर्षों के निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया, दरों के प्रकाशन और ठेकेदारों को किए गए भुगतान की जांच कराने की बात कही गई।

ज्ञापन में मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई, वार्ड क्रमांक 9 में सडक़ निर्माण, बरौंधा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया तथा बाणसागर परियोजना से विस्थापितों को आवंटित भूमि से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। कांग्रेस ने पोषण एवं सिंचाई परियोजनाओं



का लाभ क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाने और खुटखुरिया तालाब के सौंदर्यीकरण व गहरीकरण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ब्यौहारी सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई। पेयजल की गुणवत्ता सुधारने, पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न और पेंशन दिलाने तथा अवैध रेत निकासी एवं शराब बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और जनसमस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।

सीएमओ को हटाने की कवायद की चर्चा

ब्यौहारी नगर परिषद में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर खींचतान

आवक-जावक रजिस्टर और भुगतान संबंधी फाइलों को लेकर उठे सवाल

शहडोल।

जिले की ब्यौहारी नगर परिषद में इन दिनों प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निर्वाचित परिषद के अध्यक्ष तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नगर परिषद के कामकाज में कथित हस्तक्षेप, आवक-जावक रजिस्टर को अध्यक्ष के पास रखे जाने और भुगतान संबंधी फाइलों को लेकर उठ रहे सवालों ने निकाय की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है। मामले में प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग उठ रही है।



सीएमओ के पदभार संभालने के बाद बढ़ी खींचतान की चर्चा

नगर परिषद में पूर्व सीएमओ शरद गौतम के कार्यकाल के बाद शिवांगी पांडेय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व संभाला। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि नए सीएमओ के आने के बाद वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती बढ़ी है। इसी बीच अध्यक्ष द्वारा सीएमओ को पद से हटवाने के लिए भोपाल में प्रयास किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना बाकी है।

रजिस्टर और भुगतान की फाइलों पर सवाल

नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आवक-जावक रजिस्टर अध्यक्ष के पास रखा गया है। वहीं, भुगतान से जुड़ी फाइलों को भी अपने पास रखने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार, इससे कार्यालयीन कामकाज और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

नियमों के पालन और विकास कार्यों पर नजर

मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा अधिनियम, 2018 के प्रावधानों तथा प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) के प्रस्तावों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासनिक खींचतान का असर जनहित से जुड़े कार्यों पर नहीं पडऩा चाहिए। अब निगाहें जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग की भूमिका पर हैं। जरूरत है कि संबंधित अभिलेखों की जांच कराई जाए, अध्यक्ष और सीएमओ दोनों का पक्ष लिया जाए तथा वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि नगर परिषद का कामकाज नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से संचालित हो सके।

शहडोल में 11 अक्टूबर को होगा ग्रैंड गरबा महोत्सव ,सिंधु महिला शक्ति समिति ने किया आमंत्रित

शहडोल। सिंधु महिला शक्ति समिति, शहडोल के तत्वावधान में रविवार 11 अक्टूबर को ग्रैंड गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में गरबा और डांडिया रास के माध्यम से उत्सव का माहौल बनेगा। समिति ने शहरवासियों को सपरिवार शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती एस. थारवानी उपस्थित रहेंगी। वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती पूजा विसनदासानी तथा पूर्व पार्षद श्रीमती मधु चेलानी शामिल होंगी।

ब्लैक स्पॉट पर हादसों का खतरा बरकरार

नोटिस के बाद भी दो मंजिला भवन में निर्माण जारी

शेड तोडऩे में तत्परता, मुख्य भवन पर कार्रवाई कब

एनएचएआई के पत्राचार के बावजूद जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल

शहडोल। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के पकरिया-जैतपुर चौराहे पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन सडक़ सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इस स्थान पर कथित अतिक्रमण के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। जिस दो मंजिला भवन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में हाईवे की निर्धारित सीमा के भीतर बताते हुए यातायात और दृश्यता के लिए बाधक माना था, वहां अब भी निर्माण संबंधी गतिविधियां जारी होने की जानकारी सामने आई है। ताजा तस्वीर में भवन के बाहर निर्माण सामग्री बिखरी दिखाई दे रही है। साथ ही, भवन के बाहर खाना बनाने के लिए भट्टी तैयार किए जाने की बात सामने आई है। इससे चौराहे पर लोगों की आवाजाही बढऩे और दुर्घटना की आशंका को लेकर चिंता गहरा गई है।

एनएचएआई के पत्र में 45 मीटर की सीमा का उल्लेख

एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रीवा ने 15 जुलाई 2026 को पत्र जारी कर पकरिया-जैतपुर चौराहे पर निर्माण के संबंध में वैधानिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध



किया था। पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के चैनेज क्रमांक 159+400 पर स्थित निर्माण सडक़ की 45 मीटर राइट ऑफ वे सीमा के भीतर पाया गया। सडक़ के केंद्र से दोनों ओर 22.50 मीटर तक की भूमि इस सीमा में आती है। पत्र में भवन स्वामियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने का भी उल्लेख है।

शेड तोड़ा, मुख्य भवन पर कार्रवाई अब भी लंबित

मामले में शिकायतों और समाचार प्रकाशन के बाद आसपास की दुकानों के आगे निकले शेड तोड़े गए, लेकिन चौराहे के कोने पर स्थित दो मंजिला भवन अब भी खड़ा है। सवाल यह है कि जब सडक़ सीमा और दृश्यता को लेकर एनएचएआई ने आपत्ति दर्ज की है, तो मुख्य निर्माण के मामले में कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही? नोटिस जारी होने के बाद भी यदि निर्माण गतिविधियां जारी हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

ब्लैक स्पॉट पर हादसों का रिकॉर्ड जांचने की जरूरत

स्थानीय स्तर पर इस चौराहे को दुर्घटना संभावित स्थल यानी ब्लैक स्पॉट बताते हुए लगातार चिंता जताई जा रही है। यहां पहले भी सडक़ दुर्घटनाएं होने की बात कही गई है। इन घटनाओं की वास्तविक स्थिति और संख्या की पुष्टि संबंधित थाने के दुर्घटना रिकॉर्ड से की जा सकती है। ऐसे संवेदनशील स्थान पर भवन के कारण दृश्यता प्रभावित होने की आशंका को नजरअंदाज करना राहगीरों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करता है।

एसडीएम जैतपुर से लेकर कलेक्टर तक जवाबदेही तय हो

मामले में तहसीलदार बुढ़ार के स्तर पर निरीक्षण और शिकायतों के बावजूद ठोस नतीजा सामने नहीं आने पर अब एसडीएम जैतपुर, शहडोल कलेक्टर, पुलिस विभाग और एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मांग है कि एनएचएआई और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम तत्काल सीमांकन करे, थाने से दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड लेकर स्थल की संवेदनशीलता का आकलन करे और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शेड हटाने के बाद मुख्य भवन पर कार्रवाई कब होगी? यदि निर्माण वास्तव में हाईवे की निर्धारित सीमा में है और दुर्घटना का जोखिम बढ़ा रहा है, तो केवल नोटिस जारी कर मामले को लंबित रखना पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारियों को वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद न खुले।

नवरात्रि में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक





शहडोल। आगामी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी पर्व को आपसी भाईचारे, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के बुढ़ार थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों और नगर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुविधा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह सबसे प्रमुख फैसला लिया गया कि पावन नवरात्रि पर्व के पूरे नौ दिनों तक नगर क्षेत्र में मांस एवं मटन की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चौराहों पर तृतीय नेत्र की नजर, लगेगा सीसीटीवी

नगर में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए व्यापारी संघ के सहयोग से मुख्य चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गुप्त कैमरे (सीसीटीवी) लगाए जाएंगे। इसके अलावा, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाएगी।

प्रतिमा विसर्जन कुंड में करने का आह्वान

पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी देवी उत्सव समितियों से आग्रह किया है कि वे मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित विसर्जन कुंडों में ही करें। साथ ही, विसर्जन यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान नशे का सेवन करने वाले या उपद्रव मचाने वाले तत्वों को जुलूस से दूर रखने की जिम्मेदारी आयोजकों को सौंपी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन अनिवार्य

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पंडालों और विसर्जन यात्राओं में तीव्र ध्वनि वाले बाजों (डीजे) और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। तय सीमा से अधिक आवाज में बाजे बजाने पर संबंधित संचालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित

इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धनपुरी अनुभाग विकास पाण्डेय, तहसीलदार मनोज सिंह, अनुविभागीय अधिकारी अभिनव मिश्रा, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी तथा थाना प्रभारी खेम सिंह पेंड्रो प्रमुख रूप से मंच पर मौजूद रहे। इनके अलावा बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता विकास एवं हिमांशु, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि, विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी और नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और समिति पदाधिकारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे सभी पर्वों को पारंपरिक सौहार्द, शांति और शासन के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए मनाएंगे।

नगर परिषद मानपुर में चार साल के निर्माण-खरीदी कार्यों पर सवाल

उपाध्यक्ष व पार्षदों ने कलेक्टर से मांगी उच्चस्तरीय तकनीकी-आर्थिक जांच

30 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-अनशन की चेतावनी

मानपुर।

नगर परिषद मानपुर में पिछले चार वर्षों के दौरान कराए गए निर्माण, विकास एवं खरीदी कार्यों को लेकर परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी पटेल सहित वार्ड 12 की पार्षद पुष्पा शारदा गौतम ने गंभीर वित्तीय एवं तकनीकी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पार्षदों ने कलेक्टर उमरिया को शिकायती पत्र सौंपकर स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय तकनीकी तथा वित्तीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शहडोल संभाग को भी भेजी गई है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नगर परिषद में सीसी रोड, बीटी रोड, नाली निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, चिल्ड्रन पार्क, स्वागत गेट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत सामग्री, हैंडपंप, वृक्षारोपण, कुओं के जीर्णोद्धार, सार्वजनिक शौचालय, दाह संस्कार के लिए लकड़ी तथा वाहन खरीदी सहित विभिन्न कार्यों में स्वीकृत राशि और मौके पर हुए वास्तविक कार्यों के बीच अंतर है। कई कार्यों को अधूरा, गुणवत्ताहीन अथवा अपेक्षित उपयोगिता के अनुरूप नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

19 बिंदुओं पर जांच की मांग

शिकायत में चार वर्षों के दौरान कराए गए विभिन्न कार्यों की बिंदुवार जांच की मांग की गई है। इनमें सीसी एवं बीटी सडक़ों की लागत, गुणवत्ता, माप पुस्तिका (एमबी) और भुगतान का सत्यापन, नाली निर्माण की स्वीकृति एवं वास्तविक लंबाई-गुणवत्ता की जांच शामिल है।इसके अलावा तालाब सौंदर्यीकरण, चिल्ड्रन पार्क एवं स्वागत गेटों पर हुए खर्च, निविदा प्रक्रिया, सामग्री की आपूर्ति और वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है। सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और भुगतान का भी मौके पर सत्यापन कराने की मांग रखी गई है। शिकायत में तालाबों को लीज पर दिए जाने, पुराने कुओं के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण में पौधों की संख्या एवं खरीदी, हैंडपंपों की वास्तविक स्थिति तथा दाह संस्कार की लकड़ी की खरीदी-वितरण से संबंधित बिल, स्टॉक और हितग्राहियों के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई है।

स्ट्रीट लाइट और वाहनों की खरीदी भी जांच के दायरे में

पार्षदों ने स्ट्रीट लाइट, एलईडी, प्रोजेक्टर, पोल एवं अन्य विद्युत सामग्री की जीईएम/निविदा



प्रक्रिया, दर, मात्रा, आपूर्ति और स्थापना का सत्यापन कराने की मांग की है। वहीं नगर परिषद द्वारा खरीदे गए वाहनों की खरीदी प्रक्रिया, भुगतान, लॉगबुक, ईंधन और मरम्मत पर हुए खर्च की भी जांच की मांग की गई है।शिकायत में परिषद की बैठकों की संख्या एवं कार्यवाही, नियमित बैठकें नहीं होने के कारणों तथा पीआईसी से स्वीकृत कार्यों की वार्डवार जांच कराने की मांग भी की गई है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ कार्य पीआईसी सदस्यों के वार्डों में अपेक्षाकृत अधिक कराए गए हैं, जिसका नियमानुसार परीक्षण होना चाहिए।

निजी पहुंच मार्ग में शासकीय राशि खर्च करने का आरोप

शिकायत में नगर परिषद अध्यक्ष के वार्ड सहित उनके खेत अथवा निजी पहुंच मार्ग तक शासकीय राशि से सडक़ निर्माण कराए जाने के आरोपों की भी जांच की मांग की गई है।इसके लिए कार्य की स्वीकृति, लागत, उपयोगिता और सार्वजनिक हित का परीक्षण कराने की मांग की गई है।इसके साथ ही अधूरे, अनुपयोगी अथवा गुणवत्ताहीन कार्यों का तकनीकी अधिकारियों से मौके पर सत्यापन तथा प्रत्येक कार्य की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश, एमबी, बिल-वाउचर, भुगतान और पूर्णता प्रमाण-पत्र का वास्तविक कार्य से मिलान कराने की मांग की गई है।

बस स्टैंड और गीता भवन के स्थल चयन पर भी सवाल

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सामान्य सभा के प्रस्ताव एवं आम सहमति के बिना बस स्टैंड, गीता भवन सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों का चयन किया गया। इस मामले में भी संबंधित अभिलेखों एवं निर्णय प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है।वहीं संपत्ति कर निर्धारण को लेकर भी शिकायत में सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नागरिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण किया जाना चाहिए था, लेकिन बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के अधिकतम दरों पर संपत्ति कर लगाए जाने तथा पूर्व वर्षों के संपत्ति कर को माफ किए जाने के मामले की भी जांच आवश्यक है।

मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

पार्षदों ने मांग की है कि जांच नगर परिषद के स्थानीय अधिकारियों से न कराकर जिला अथवा संभाग स्तर के स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय अधिकारियों की समिति से कराई जाए। साथ ही जांच पूरी होने तक परिषद एवं पीआईसी से संबंधित मूल अभिलेख, फाइलें, कार्यवाही पुस्तिकाएं, एमबी, बिल-वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, निविदा दस्तावेज और वाहन लॉगबुक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं।

30 दिन में जांच नहीं तो आंदोलन

शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर उक्त शिकायतों की जांच शुरू नहीं की गई तो समस्त पार्षद धरना-प्रदर्शन एवं आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ऐसा शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है। शिकायत पत्र पर नगर परिषद उपाध्यक्ष गीता देवी पटेल सहित वार्ड क्रमांक 12, 10, 13 और 04 के पार्षदों के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित हैं।शिकायतकर्ताओं के आरोपों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

पाली में हरी पत्तियों की बंपर बहार

नवागत एसडीओपी से कार्यवाही की दरकार

उमरिया। कोयलांचल और आस्था की नगरी के नाम से मशहूर बिरसिंहपुर पाली इन दिनों एक नए और खौफनाक कारोबार के लिए सुर्खियों में है। नगर का वार्ड क्रमांक 12 हो या झिरिया मोहल्ला, हर तरफ एक खास किस्म की सुलगती खुशबू हवाओं में जहर घोल रही है। पुराने अड्डे भले ही ठिकाना बदल चुके हों, लेकिन नशे का यह काला खेल अब दुगुनी रफ्तार से फल-फूल रहा है। कभी एक वार्ड की गलियों तक सीमित रहने वाला यह धंधा अब स्वागत गेट से लेकर सूखा धौरई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। आलम यह है कि इलाके के गली-कूचों में कानून के पहरेदारों की कथित रहमत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं।

संरक्षण का छत्र और बदलती लोकेशन

सूत्रों की मानें तो बीते दिनों पुलिसिया कार्रवाई का थोड़ा-बहुत असर तो दिखा था, लेकिन नशे के सौदागरों के हौसले पस्त होने के बजाय और बुलंद हो गए। रणनीति बदली, मोहरे बदले और नया ठिकाना तैयार हो गया। चर्चा है कि मुन्नी के खास संरक्षण के साए में अब नए-नए मोहरों को आगे कर इस पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। स्वागत गेट के आसपास मंडराती संदिग्ध गतिविधियां हों, झिरिया मोहल्ले का चर्चित ठिकाना हो या फिर सूखा धौरई का इलाका हर जगह हरे जहर की पुडिय़ा आसानी से उपलब्ध होने की चर्चाएं आम हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शाम ढलते ही इन इलाकों में संदिग्धों का जमावड़ा लगने लगता है, जो देर रात तक बना रहता है।



बर्बादी की कगार पर भविष्य

नशे के इस संगठित मकडज़ाल का सबसे खौफनाक और चिंताजनक पहलू यह है कि इसकी चपेट में नगर की मासूम युवा पीढ़ी आ रही है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले नौजवानों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक को इस दलदल में धकेला जा रहा है। चंद पैसों के फायदे के लिए नशे के सौदागर युवाओं का भविष्य गर्त में ढकेल रहे हैं। कई परिवार इस लत के कारण भुखमरी और घरेलू कलह के शिकार होकर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। जिस उम्र में युवाओं के हाथों में किताबें और भविष्य के सपने होने चाहिए, उस उम्र में वे नशे की गर्त में समाते जा रहे हैं। स्थानीय अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गहरे खौफ और चिंता में रातें गुजारने को मजबूर हैं।

वर्दी पर दाग या खाकी की अनदेखी

जनचर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म है कि क्या वाकई यह पूरा खेल स्थानीय प्रशासन की नजरों से ओझल है? या फिर सफेदपोश और खाकी के कुछ कथित तत्वों की मौन सहमति इस काले कारोबार को ऑक्सीजन दे रही है? जब सरेराह अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हों, तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि बिना किसी अंदरूनी शह के इतना बड़ा नेटवर्क बेखौफ तरीके से नहीं चलाया जा सकता। आखिर क्यों बार-बार शिकायत के बावजूद स्थायी रूप से इस तंत्र को ध्वस्त नहीं किया जा रहा, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

नवागत एसडीओपी से जगी उम्मीद की किरण

क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशे के जाल को देखते हुए अब स्थानीय नागरिकों, समाजसेवियों और पीड़ित परिवारों की निगाहें नवागत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पर टिक गई हैं। जागरूक नागरिकों ने नवागत अधिकारी से गुहार लगाई है कि वे इस पूरे मामले को स्वयं संज्ञान में लें और निष्पक्ष जांच कराकर नशे के इस संगठित ढांचे पर करारा प्रहार करें। अब देखना यह होगा कि नवागत पुलिस कमान इस अवैध तंत्र की रीढ़ तोडक़र नगर को नशे के इस काले साए से मुक्त करा पाती है, या फिर साहब की कार्रवाई भी केवल फाइलों और बयानों तक ही सिमटकर रह जाएगी। फिलहाल, पाली की जनता कानून के एक कड़े और सख्त रुख का इंतजार कर रही है।

हत्या का आरोपी 15 दिन से जेल में पर खाकी और कलम के साहब बेखबर

जनजातीय कार्य विभाग की कुंभकर्णी नींद पर उठे सवाल

शहडोल। कानून की किताबों में दर्ज नियम-कायदों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसका जीता-जागता नमूना इन दिनों शहडोल के जनजातीय कार्य विभाग में देखने को मिल रहा है। हत्या जैसे जघन्य अपराध में सलाखों के पीछे पहुंचे एक शासकीय कर्मचारी पर अब तक विभागीय मेहरबानी बरस रही है। सीधी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी की कलम से निलंबन का आदेश नहीं निकल सका है। इस अजीबो-गरीब प्रशासनिक सुस्ती ने सहायक आयुक्त की कार्यप्रणाली को सीधे कठघरे में खड़ा कर दिया है।

हत्या की धारा और 48 घंटे का नियम

मामला दरैन खारिका टोला थाना सीधी निवासी कौशल प्रसाद रैदास से जुड़ा है। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, आरोपी को थाना सीधी में धारा 103(1) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत 23 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन दोपहर में उसे जेएमएफसी न्यायालय जयसिंहनगर के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। प्रशासनिक नियमों का स्पष्ट फरमान है कि यदि कोई शासकीय सेवक 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक या पुलिस हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाता है। परंतु यहां 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आधी सदी जैसा वक्त बीत जाने के बाद भी सहायक आयुक्त कार्यालय की सुस्त फाइलों में कोई हलचल नहीं हुई।

क्या रसूख रोक रहा आदेश या प्रक्रिया में जानबूझकर ढील

जनचर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर इतनी बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन है? क्या विभाग को गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना ही नहीं मिली, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं? यदि पुलिस ने गिरफ्तारी की लिखित सूचना परिजनों को दी और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी हुई, तो फिर विभाग तक यह खबर पहुंचने में कौन सा अदृश्य अवरोध आड़े आ रहा है? कानूनन भले ही अदालत का फैसला आना बाकी हो, लेकिन हत्या की संगीन धारा के आरोपी पर अनुशासनात्मक प्रहार न होना कई तरह के संदेहों को जन्म दे रहा है।

उच्चाधिकारियों के संज्ञान का इंतजार

जिले के जागरूक नागरिकों और प्रशासनिक हलकों से अब यह पुरजोर मांग उठने लगी है कि वरिष्ठ अधिकारी इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाएं। सवाल सिर्फ एक निलंबन आदेश का नहीं, बल्कि शासकीय सेवा की शुचिता और नियमों के इकबाल का है। क्या किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद 15 दिनों तक फाइल दबाकर रखना महज प्रक्रियात्मक देरी है या इसके पीछे किसी का वरदहस्त है? अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद जनजातीय कार्य विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटती है या फिर जिम्मेदार अधिकारी कागजी बहानों की आड़ लेकर इस विफलता पर पर्दा डालने का प्रयास करते रहेंगे।

नवरात्रि से पहले नगर पालिका अलर्ट, अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज

छोटे दुकानदारों में नाराजगी, गरीबों को हटाने और रसूखदारों को संरक्षण देने के आरोप

दुकानें हटने के बाद उन्हीं जगहों पर खड़े हो रहे चारपहिया वाहन

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नवरात्रि पर्व नजदीक आते ही कोतमा नगरपालिका प्रशासन ने नगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है। गुरुवार और शुक्रवार को नगरपालिका अमले ने नगर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण कर सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने और दुकानों के बाहर तक फैलाए गए सामान को जब्त करने की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई ने छोटे दुकानदारों के बीच नाराजगी भी बढ़ा दी है। गरीब फल-सब्जी विक्रेताओं ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि व्यवस्था के नाम पर उन्हें तो हटाया जाता है, लेकिन रसूखदारों के खिलाफ वैसी सख्ती नजर नहीं आती। नगरपालिका की टीम ने गांधी चौक, स्टेशन चौक, पुराना अस्पताल रोड, एसबीआई रोड और पंचायती मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क तक दुकानें फैलाकर सामान रखने वाले दुकानदारों के सामान और दुकानों के बाहर लगाए गए पटिए-फट्टे जब्त किए गए। यातायात बाधित करने वाले वाहनों को हटाने की कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा सब्जी और फल विक्रेताओं को प्रमुख मार्गों से हटाकर बाजार के बाहर स्थानांतरित किया गया, ताकि नवरात्रि के दौरान भीड़ और जाम की स्थिति से बचा जा सके। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर विवाद की स्थिति भी बनी।

नगरपालिका की कार्रवाई से नाराज फल एवं सब्जी विक्रेता शंभू केवट, रामशरण, सोनू अग्रवाल, विनोद साह और लीला बाई ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटे व्यापारियों को बार-बार परेशान किया जाता है। उनका कहना है कि ठेले और दुकानें हटाए जाने के बाद उन्हीं स्थानों पर चारपहिया वाहन खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सवाल



उठता है कि यदि सड़क पर वाहन खड़े होने से यातायात बाधित होता है, तो उनके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? छोटे व्यापारियों का कहना है कि वे अपनी आजीविका चलाने के लिए ठेले और छोटी दुकानें लगाते हैं। उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था और निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि कार्रवाई का दबाव मुख्य रूप से गरीब दुकानदारों पर दिखाई देता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामले में प्रशासन का रवैया अलग नजर आता है। हालांकि, रसूखदारों को संरक्षण देने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नवरात्रि के दौरान सुचारु यातायात और नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना नगरपालिका की जिम्मेदारी है। सड़क पर अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग, दोनों ही आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे में कार्रवाई तभी प्रभावी मानी जाएगी, जब नियमों का पालन सभी पर समान रूप से कराया जाए। केवल छोटे दुकानदारों को हटाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, यदि उसी स्थान पर दोबारा वाहन खड़े होने लगें। अब सवाल यह है कि क्या नगरपालिका प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण के साथ-साथ अवैध या बाधक पार्किंग पर भी लगातार कार्रवाई करेगी? क्या छोटे व्यापारियों के लिए व्यवस्थित वैकल्पिक स्थान तय किए जाएंगे? और क्या प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों का पालन गरीब दुकानदारों से लेकर प्रभावशाली लोगों तक सभी को समान रूप से करना पड़े? नवरात्रि से पहले शुरू हुई इस मुहिम की वास्तविक सफलता कार्रवाई की संख्या से नहीं, बल्कि नगर की सड़कों पर व्यवस्था कायम रहने और आम नागरिकों को राहत मिलने से तय होगी।



भालूमाड़ा पुलिस की रेत चोरों पर कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। अनूपपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भालूमाड़ा पुलिस ने गोडारू नदी के मनटोलिया घाट के पास कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों से कुल चार घन मीटर रेत बरामद की है। जब्त वाहनों और रेत की कुल कीमत 9 लाख 6 हजार रुपये बताई गई है। मामले में वाहन चालकों और वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर को भालूमाड़ा पुलिस की टीम ने गोडारू नदी के मनटोलिया घाट के पास अवैध रूप से रेत का परिवहन करते दो ट्रैक्टर पकड़े। इनमें नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर तथा लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर शामिल है। दोनों वाहनों के साथ ट्रॉलियों में लदी दो-दो घन मीटर रेत जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में सीताराम केवट, निवासी सरइयाटोला देवरी, वाहन मालिक लक्ष्मीकांत केवट, निवासी पथरोड़ी, थाना कोतमा तथा रामअवतार मिश्रा, निवासी चटहाटोला और संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रकरण में अपराध क्रमांक 305/26 और 306/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2), खनिज अधिनियम की धारा 4/21 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 (3)/177 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर विक्रांत मुराब के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम तथा एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के मार्गदर्शन में अवैध खनन, रेत चोरी और अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी भालूमाड़ा निरीक्षक राधिका भगत की प्रमुख भूमिका रही। पुलिस टीम में ईश्वर यादव, जितेन्द्र खलखो, मकसूदन सिंह, प्रवीण भगत और चालक दिनेश किराडे शामिल रहे। नदी घाटों से खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिहाज से गंभीर विषय है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने मामले में जब्त वाहनों और रेत के संबंध में वैधानिक कार्रवाई करते हुए विवेचना आगे बढ़ाई है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत जमुना बस्ती में पौधारोपण, पौधों के संरक्षण का लिया संकल्प



हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशन में विकासखंड अनूपपुर के सेक्टर क्रमांक 04 अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र, जमुना बस्ती में सेवा संकल्प अभियान के तहत 'सेवा मेरा योगदान' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलदार पौधों का रोपण किया गया। साथ ही लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना और समाज में हरियाली के महत्व का संदेश प्रसारित करना रहा। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था एवं नगर विकास प्रस्फुटन समिति पसान के प्रतिनिधियों, जमुना, भालूमाड़ा एवं परासी की समितियों के सदस्यों, परामर्शदाता शिवानी सिंह, सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता की। सभी सहभागियों ने पौधारोपण को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सेवा, समर्पण और जनसहभागिता के माध्यम से आयोजित इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में हरित वातावरण विकसित करना तथा लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना रहा।

पूर्व पार्षद प्रत्याशी सुनीता सिंह के निवास पर धार्मिक आयोजन

पुष्पराजगढ़ विधानसभा प्रभारी पं. जानकी प्रसाद मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों ने की पूजा-अर्चना

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 कपिला संगम अमरकंटक की पार्षद प्रत्याशी सुनीता सिंह के निज निवास पर पूर्वजों की पावन स्मृति में विविध धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। आयोजन के अंतर्गत गौरी-गणेश एवं गंगा पूजन, हवन, संगीतमय सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या तथा जागरण का आयोजन हुआ। धार्मिक कार्यक्रम में पुष्पराजगढ़ विधानसभा प्रभारी पं. जानकी प्रसाद मिश्रा विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ मंडल अध्यक्ष श्यामलाल सेन, जिला उपाध्यक्ष हरि सिंह उईके तथा युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बिरू तंबोली भी उपस्थित रहे। सभी ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की और आयोजक परिवार को अपनी शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान भजन-संध्या एवं सुंदरकांड पाठ से वातावरण भक्तिमय बना रहा। उपस्थित जनों ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में सहभागिता करते हुए आयोजक परिवार के साथ स्नेहपूर्वक भोजन-प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पूर्वजों की स्मृति में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान को श्रद्धा, संस्कार और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बताया।



खबर संक्षेप

सौरभ शुक्ला बने सांसद प्रतिनिधि



ब्यौहारी। पंडित राम किशोर शुक्ला शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के जन भागीदारी पुनर्गठन में सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने शासकीय महाविद्यालय में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, सौरभ शुक्ला पिता मिथिलेश शुक्ला निवासी वार्ड नंबर 13 ब्यौहारी- को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया महाविद्यालय में होने वाली प्रशासनिक बैठकों में सांसद प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होंगे उनकी नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं उनके शुभचिंतकों को ने खुशी व्यक्त की है

5 नवंबर तक होगा कोदो-कुटकी उपार्जन के लिये पंजीयन

कटनी। खरीफ वर्ष 2026 में कोदो-कुटकी के उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कोदो-कुटकी की बोनी करने वाले किसानों से अपनी फसल की गिरदावरी समय पर कराने की अपील की है, ताकि वे ई-उपार्जन पोर्टल पर अपनी उपज का पंजीयन करा सकें और उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2026 में ई-उपार्जन पोर्टल पर कोदो एवं कुटकी के उपार्जन के लिए कृषक पंजीयन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कटनी जिले का चयन कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए किया गया है। जिले में विगत वर्षों में भी कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जाता रहा है। कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषकों का पंजीयन 5 नवंबर तक किया जाएगा। कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने अपने खेतों में कोदो अथवा कुटकी की बोनी की है, वे संबंधित हल्का पटवारी के माध्यम से अपनी फसल की गिरदावरी अवश्य कराएं। गिरदावरी दर्ज होने के बाद किसान कोदो-कुटकी फसल का पंजीयन कराकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी उपज का उपार्जन करा सकेंगे।

बीज रोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश

स्लीमनाबाद। बहोरीबंद वन विभाग कार्यालय से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहाँ बात सिर्फ ड्यूटी की नहीं, बल्कि सेवा के संकल्प की है। वन परिक्षेत्र बहोरीबंद कार्यालय मै सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत वृहद स्तर पर साफ-सफाई अभियान चलाया गया।वन परिक्षेत्र बहोरीबंद के समस्त स्टाफ और वन सुरक्षा श्रमिकों ने मिलकर पूरे प्रांगण से पॉलीथीन, डिस्पोजल आइटम, झाड़ियां, कचरा और घास को साफ कर उसका निस्तारण किया।सिर्फ सफाई ही नहीं, पर्यावरण को हरा-भरा बनाने के लिए परिक्षेत्र अधिकारी देवेश गौतम, सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेश गुप्ता और स्टाफ द्वारा प्रांगण में बीजा के पौधों का रोपण भी किया गया।इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण और वनों को अवैध कटाई, अवैध अग्नि जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखने और बचाने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेश गौतम, सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेश गुप्ता सहित समस्त परिक्षेत्र सहायक, वनरक्षक, स्थायीकर्मी और सुरक्षा श्रमिकों की उपस्थिति रही।

रेत के अवैध परिवहन पर ट्रैक्टर-ट्रॉली किया जब्त

कटनी। अवैध रेत खनन एवं परिवहन के खिलाफ बरही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम झिरिया से लगे क्षेत्र में रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद थाना बरही परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम झिरिया क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है।

बुढ़ार में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाए जाएंगे नवरात्रि व दशहराः कानून-व्यवस्था पर रहेगा जोर

बुढ़ार। आगामी नवरात्रि, दशहरा एवं गरबा आयोजनों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों के दौरान शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने, धार्मिक आयोजनों में आपसी समन्वय और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

यह बैठक तहसीलदार संदीप बघेल, नायब तहसीलदार मनोज सिंह, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDOP) विकास पाण्डेय, थाना प्रभारी खेम सिंह प्रेंद्रो, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक शिवेंद्र द्विवेदी एवं जिला उपाध्यक्ष दौलत मनमानी की उपस्थिति में संपन्न हुई।

सुरक्षा व व्यवस्था के लिए प्रमुख निर्णयः CCTV कैमरों के लिए सहयोगः व्यापारी संघ एवं



सिंधी समाज के अध्यक्ष दौलत मनमानी ने नगर के 4 प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु पुलिस को 40 हजार रुपये की सहयोग राशि देने की घोषणा की।

यातायात व नो-एंट्रीः नवरात्रि के दौरान शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। कोतमा रोड मार्ग पर वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।

डीजे पर समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशानुसार डीजे एवं साउंड सिस्टम का संचालन केवल रात्रि 10 बजे तक ही अनुमत होगा।

मांस विक्रय स्थल बदलाव

त्योहारों के दौरान मांस विक्रय के स्थलों को परिवर्तित करने पर सहमति बनी।



गश्त व सुरक्षाः जैतपुर चौराहा, रेलवे स्टेशन मार्ग और बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग टीम तैनात रहेगी। बैठक में नगर निरीक्षक खेम सिंह प्रेंद्रो ने सभी वर्गों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने नागरिकों को अफवाहों से बचने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए। इस दौरान राकेश पांडेय, पत्रकार आशीष नामदेव, हिमांशु पाण्डेय (MPEB), राधिका तिवारी, पार्षद मोहन बैगा, प्रशांत जैन, दिलीप जैन, अनामिका सिंह, अर्जुन सोनी, राम एस मनाली, अविनाश गुप्ता, सतपाल गिवलानी, मनोज गुप्ता, सोहन लाल, रणधीर कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर कटकोना में भाजपाइयों ने रोपे 76 पौधे, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिया 'एक पेड़ मां के नाम' का संदेश



बुढ़ार। भारतीय जनता पार्टी मंडल बुढ़ार द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 76 वें जन्मदिवस के सुअवसर पर ग्राम पंचायत कटकोना स्थित माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिसर में 76 फलदार व छायादार पौधे रोपे गए और पौधरोपण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की सहर्ष शुभकामनाएं प्रेषित की गई।



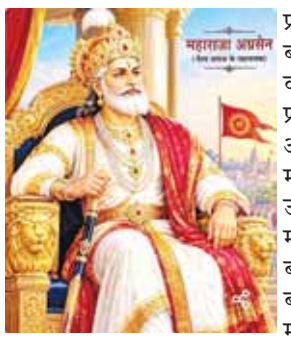
हरियाली महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जयसिंह मरावी रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण एवं पौधरोपण के महत्व पर विशेष जोर दिया। इस दौरान उपस्थित सभी अतिथियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केवल पौधे लगाने ही नहीं, बल्कि उनके नियमित संरक्षण और संवर्धन का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष राकेश पाण्डेय, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कैलाश विशनानी, सेवा संकल्प अभियान के जिला नोडल अधिकारी व जन अभियान परिषद के जिला कोऑर्डिनेटर विवेक पांडे, DPO अहिरवार, भाजपा मंडल बुढ़ार अध्यक्ष अर्जुन सोनी, जनपद उपाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त आनंद सिन्हा, जनपद पंचायत सीईओ राजीव लघाटे, MPEB JE विकास, विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिलीप निगम एवं विकासखंड उद्यानिकी अधिकारी राजेंद्र रायकवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा शक्ति केंद्र प्रभारी ज्ञान सिंह, पंकज सिंह, राहुल शर्मा, प्रशांत पांडे, बूथ अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह बघेल, पूर्व जिला महामंत्री (ओबीसी मोर्चा) भागचंद सोनी, अनिल सिंह, सरपंच साजन बैगा, थानेश्वर केवट, नरेन्द्र बरगही, विश्वनाथ त्रिपाठी, अधीक्षिका रीता श्याम,सीताराम दुबे, प्राचार्या वर्षा दुबे, तथा स्थानीय समाजसेवियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम में माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्राओं ने भी अत्यधिक उत्साह दिखाया। छात्राओं ने अतिथियों के साथ मिलकर पौधे रोपे और पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। भाजपा मंडल बुढ़ार द्वारा आयोजित इस प्रयास के जरिए प्रकृति संरक्षण, हरियाली संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण निर्मित करने का मजबूत संदेश दिया गया।

धनपुरी में आज से गूंजेगा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का उल्लास

11 अक्टूबर को निकलेगी भव्य शोभायात्रा

धनपुरी। सेवा, सद्भाव, सामाजिक समरसता और जनकल्याण की प्रेरणा देने वाले महाराजा अग्रसेन जी की 5150वीं जयंती पर कोयलांचल नगरी धनपुरी में आज से उत्सव का उल्लास छाएगा। अग्रवाल समाज के तत्वावधान में 10 एवं 11 अक्टूबर को श्यामा गार्डन में दो दिवसीय जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक रंगों और पारिवारिक सहभागिता से सजे इस आयोजन में समाज की एकता और गौरवशाली परंपरा की झलक देखने को मिलेगी।



महोत्सव का विशेष आकर्षण 11 अक्टूबर को श्री राधाकृष्ण मंदिर से निकलने वाली भव्य शोभायात्रा होगी, जिसमें बैंड-बाजे के साथ महाराजा अग्रसेन जी का जयघोष नगर के प्रमुख मार्गों पर गूंजेगा।

शोभायात्रा से सजेगी नगर की राह, महाआरती में जुटेगा समाज

महोत्सव के दूसरे दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे श्री राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण से महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। बैंड-बाजे के साथ निकलने वाली शोभायात्रा आजाद चौक, माइकल चौक सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्यामा गार्डन पहुंचेगी। शोभायात्रा के माध्यम से महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों, सामाजिक एकता और सेवा भावना का संदेश दिया जाएगा। श्यामा गार्डन में शाम 6 बजे महाराजा अग्रसेन जी की महाआरती होगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। आयोजन को लेकर अग्रवाल समाज में उत्साह का माहौल है। आयोजकों ने समाज के सभी परिवारों से शोभायात्रा में शामिल होकर महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की है।

बच्चों की प्रतिभा, महिलाओं के हुनर और परिवारों के उत्साह का संगम

10 अक्टूबर को शाम 4 बजे से श्यामा गार्डन में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों के लिए जूनियर और सीनियर वर्ग में अलग-अलग गतिविधियां एवं प्रस्तुतियां रखी गई हैं। वहीं महिलाओं और पुरुषों के लिए खेलकूद तथा मनोरंजक प्रतियोगिताओं के माध्यम से उत्सव को पारिवारिक रंग दिया जाएगा। महिला मंडल अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को मंच देना, महिलाओं को अपनी कला और हुनर प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराना तथा समाज के परिवारों के बीच आपसी मेल-जोल और आत्मीयता को बढ़ावा देना है। दो दिवसीय आयोजन में धार्मिक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां समाज के लोगों को एक सूत्र में जोड़ेंगी।

सुभाष गुप्ता होंगे मुख्य अतिथि, बृजवासी अग्रवाल करेंगे अध्यक्षता

जयंती महोत्सव में एलआईसी बुढ़ार के पूर्व विकास अधिकारी सुभाष गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं जयंती समारोह अध्यक्ष बृजवासी अग्रवाल करेंगे। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां की गई हैं।

महाराजा अग्रसेन जी की जयंती केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समानता, सहयोग और सामाजिक एकजुटता के आदर्शों को स्मरण करने का अवसर भी है। धनपुरी में आयोजित यह दो दिवसीय महोत्सव इन्हीं मूल्यों के साथ समाज की नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देगा।

घुनघुटी में बजरंग इस्पात पावर कंपनी लाएगी विकास की सौगात, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकताः-----जीएम शशिधर द्विवेदी_

जिले के घुनघुटी में खुलेगा रोजगार का द्वार, घुनघुटी में बजरंग पावर कोल ब्लॉक का आगाज, युवाओं को मिलेगा रोजगार





उमरियाः उमरिया जिले के विकासखंड पाली अंतर्गत ग्राम घुनघुटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यहां बजरंग पावर इस्पात कोल ब्लॉक कंपनी के शुरू होने से अब क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की तलाश में बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। कंपनी के खुलने से घुनघुटी सहित पूरे पाली क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए अवसर खुलेंगे।बजरंग इस्पात पावर कोल ब्लॉक कंपनी के जीएम *शशिधर द्विवेदी* ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जिस क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। जीएम द्विवेदी ने कहा कि घुनघुटी क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ कोयला खनन करना ही नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र का समग्र विकास करना है जहाँ कंपनी कार्य कर रही है।उन्होंने बताया कि बजरंग पावर इस्पात कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार काम करेगी। कंपनी द्वारा ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, स्वच्छ पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किया जाएगा। जीएम ने आगे कहा कि कंपनी गांव के गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें कंपनी में ही रोजगार के योग्य बनाया जाएगा, ताकि पलायन पूरी तरह से रोका जा सके। वहीं कंपनी के आने की खबर से घुनघुटी, पाली, बड़वाह और आसपास के दर्जनों गांवों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से रोजगार के लिए उन्हें बिलासपुर, कोरबा और नागपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही गांव में रोजगार मिलने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि इस कोल ब्लॉक के खुलने से न सिर्फ युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा भी लिखी जाएगी और पाली विकासखंड जिले का सबसे विकसित ब्लॉक बनेगा।

शांति समिति की बैठक में त्यौहारों को लेकर हुई चर्चाएं

हरिभूमि न्यूज ⏭ बड़वारा

बड़वारा थाना परिसर में बड़वारा थाना प्रभारी सुयश पाण्डे एवम बड़वारा नायब तहसीलदार हर्षवर्धन राम टेके तथा गणमान्य जनों की उपस्थिति में शांति सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्र शामिल हुए । समस्त दुर्गा समितियों के आयोजकों ने हर्ष उल्लास के वातावरण में पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग और आपसी समन्वय बनाए रखने का संकल्प लिया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवम गणमान्य जनों ग्राम पंचायत के सरपंचों तथा आम नागरिकों ने आगामी नवरात्रि दशहरा के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के संदर्भ में पुलिस, प्रशासन स्थानीय पँचायत व जनपद पँचायत के पदधिकारियों सहित विद्युत विभाग जेई सुमित सिन्हा भी उपस्थित हुए।। दशहरा महोत्सव समिति ने विद्युत व्यवस्था,मार्गो का दुरुस्तीकरण, सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था, पुलिस की निगरानी एवं तैनाती , सुगम यातायात सहित दशहरा जुलूस मार्ग पर लाउडस्पीकर एवं कंट्रोल रूम , अनेक स्थानों की बैरिकेडिंग , पेयजल , प्रसाधन , सुविधा जनक विसर्जन की समुचित व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से व्यवस्था बैठक में दुर्गा समितियों ने मंशा व्यक्त कर इस बात पर जोर दिया है कि कि स्थानीय पुलिस व राजस्व विभाग के द्वारा नवरात्रि के पूर्व गड्ढे युक्त सड़को की मरम्मत एवं दुरुस्त कर शासन-प्रशासन के साथ संवाद, समन्वय एवं सहयोग बनाए रखते हुए दशहरा महापर्व को भव्यता और दिव्यता के साथ उत्साह पूर्वक मनाने का संकल्प लिया।

खटखारिया तालाब के मेड पर सड़क बनवाये जाने एवं हाई मास्क लाइट लगवाए जाने की मांग

ब्यौहारी। नगर परिषद द्वारा व्यवहारी की शान कहे जाने वाले खटखारिया तालाब की पूर्ण रूपेण सफाई कर दी गई है जो अच्छा दिख रहा है व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इस पर खुशी जाहिर की है और अब उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष श्री कृष्ण गुप्ता राजन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवांगी पांडे से मांग की है कि तालाब तो स्वच्छ हो गया है अब तालाब के किनारे किनारे पेपर पत्थर लगाकर रनिंग ट्रेक बना दिया जाए और कुछ बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी जाए, जिससे जो लोग सुबह-सुबह सड़कों में दौड़ते हैं वह तालाब के किनारे बने रनिंग ट्रैक में दौड़े फिटनेस भी बढ़ेगी और अच्छा दृश्य भी मिलेगा इसके अलावा तालाब के बीच में फब्बारा लगाकर लेजर लाइट डालकर शाम को रंग बिरंगा प्रकाश कराया जाए जहां पर घूमने के लिए शाम को नगर वासी अपने परिवार के साथ आ सके और अपना कुछ समय बिता सके तालाब के मद के चारों तरफ लाइट लगवाने की मांग की गई है।



स्वच्छता एवं साक्षरता का दिया संदेश

शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली में सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत स्वच्छता एवं साक्षरता का संदेश शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली में 'सेवा मेरा योगदान' अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, महाविद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा प्लास्टिक उन्मूलन जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य श्री हरलाल अहिरवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि 'सेवा मेरा योगदान' अभियान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और



उन्हें निभाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा समाज में साक्षरता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का छोटा-सा प्रयास भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शाहिद ए. सिद्दीकी के मार्गदर्शन में आयोजित इन गतिविधियों में महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ, अनुभव श्रीवास्तव डॉ मंसूर अली, डॉ jps चौहान, डॉ नरेश प्रसाद शुक्ला, डॉ त्रिभुवन गिरी, डॉ मनीषा अग्रवाल, डॉ शिवराज सिंह एवं कर्मचारीगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक उन्मूलन में सहयोग करने तथा सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।

प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़े सीएम राइज स्कूल: तीन साल में भी नहीं बन पाए भवन

2025 में पूरी होनी थी निर्माण की प्रक्रिया, अब 2026 के अक्टूबर-नवंबर तक का इंतजार

छह स्कूलों के निर्माण में डेढ़ से दो साल तक की देरी

जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने के बजाय मौखिक सख्ती तक सीमित विभाग

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। बच्चों को आधुनिक शिक्षा, बेहतर कक्षाएं और सुविधायुक्त स्कूल भवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम राइज योजना अनूपपुर जिले में प्रशासनिक उदासीनता और निर्माण कार्यों की कमजोर निगरानी का शिकार होती नजर आ रही है। वर्ष 2023 में शुरू हुए जिले के छह विद्यालयों के भवन तीन साल बीतने के बाद भी पूरी तरह तैयार नहीं हो सके हैं। किसी भवन में फिनिशिंग अधूरी है तो कहीं बहुउद्देशीय हॉल का काम बाकी है। बिजली फिटिंग, प्लास्टर, टाइल्स और खिड़की-दरवाजों जैसे जरूरी कार्यों के लिए भी विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण की निर्धारित समयसीमा वर्ष 2024-25 में ही समाप्त हो गई, लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2026 तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह देरी केवल ठेकेदारों की लेटलतीफी का मामला नहीं है, बल्कि निर्माण कार्यों की निगरानी, समयसीमा का पालन कराने और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। यदि समय पर समीक्षा होती, निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जाता और अनुबंध की शर्तों के मुताबिक कार्रवाई की जाती, तो क्या बच्चों को इतने लंबे समय तक नए भवनों से वंचित रहना पड़ता? सवाल यह भी है कि जब मूल समयसीमा बीत गई, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने निर्माण पूरा कराने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए।



समयसीमा खत्म, फिर भी निर्माण अधूरा

जिले के अमगवां, बदरा, पचखुरा (निगवानी), खुटाटोला, खोड़री और शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुष्पराजगढ़ में सीएम राइज भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन सभी भवनों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना था, लेकिन तय समय पर निर्माण पूरा नहीं हो सका। अब विभाग ने नई समयसीमाएं निर्धारित की हैं। अमगवां, बदरा, खुटाटोला और खोड़री में अक्टूबर 2026 तक तथा पचखुरा और पुष्पराजगढ़ में नवंबर 2026 तक निर्माण पूरा होने की संभावना जताई गई है। अमगवां स्कूल का निर्माण 13 दिसंबर 2024 तक पूरा होना था। सितंबर 2026 तक भी यहां फिनिशिंग और हॉल की छत से संबंधित काम बाकी था। यानी निर्धारित समयसीमा गुजरने के लगभग 22 महीने बाद भी भवन तैयार नहीं हो पाया। बदरा स्कूल को 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन सितंबर 2026 तक फिनिशिंग और बहुउद्देशीय हॉल का काम अधूरा था। विभाग ने स्वीकृत संरचनात्मक डिजाइन देर से मिलने को देरी की वजह बताया है। हालांकि, इस बाधा के बाद निर्माण की गति बढ़ाने और समयसीमा की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। पचखुरा (निगवानी) स्कूल की पूर्णता तिथि 1 जुलाई 2025 थी, लेकिन अब नवंबर 2026 तक काम पूरा होने की उम्मीद है। खुटाटोला और खोड़री के भवनों को अप्रैल 2025 तक तैयार होना था। सितंबर 2026 तक दोनों जगह काम जारी था और अक्टूबर 2026 की नई समयसीमा दी गई। वहीं, पुष्पराजगढ़ मॉडल स्कूल में सितंबर 2026 तक ब्लॉक-बी की फिनिशिंग, ब्लॉक-ए के दूसरे तल की फिनिशिंग और बहुउद्देशीय हॉल का काम प्रगतिरत था। इस भवन की पूर्णता के लिए नवंबर 2026 का लक्ष्य रखा गया है।

निगरानी पर सवाल, कौन देगा कार्रवाई का हिसाब?

निर्माण कार्यों में लगातार देरी के बावजूद विभागीय कार्रवाई की स्थिति सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने के लिए मौखिक सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन अर्थदंड या अन्य दंडात्मक कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। यदि ठेकेदार समयसीमा का पालन नहीं कर रहे थे, तो विभाग ने समय रहते अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की गई? क्या देरी के कारणों की जिम्मेदारी तय की गई? प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल निर्माण की प्रगति की जानकारी लेना नहीं, बल्कि तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा कराना भी है। ऐसे में समयसीमा बीतने के बाद नई तारीख तय कर देना अपने आप में समस्या का समाधान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक विद्यालय की देरी का कारण दर्ज हो, जिम्मेदार पक्ष की जवाबदेही तय की जाए और शेष कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

जर्जर भवनों में पढ़ाई, कब मिलेगा योजना का लाभ?

सीएम राइज स्कूलों के नए भवनों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना है। लेकिन भवन तैयार नहीं होने से पुराने और जर्जर भवनों में पढ़ाई जारी रहने की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रभात कुमार लोरिया का कहना है कि निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि कुछ कार्य नवंबर में भी पूरे होंगे। उनके अनुसार, काम लगभग पूरा हो चुका है और केवल फिनिशिंग बाकी है। अब सवाल यह है कि अक्टूबर-नवंबर की नई समयसीमा का भी पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तीन साल से चल रहे निर्माण कार्यों में देरी का हिसाब कौन देगा और बच्चों को नए भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन इस बार क्या ठोस कदम उठाएगा? इन सवालों के जवाब विभागीय दावों से नहीं, बल्कि समय पर पूरे हुए निर्माण और तय हुई जवाबदेही से ही मिलेंगे।

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ में दो नई नियुक्तियां

संजय शुक्ला को संगठन मंत्री सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी, राजेश जैन बने जिला सह-सचिव



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला इकाई अनूपपुर को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संगठन में दो नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है।

प्रदेशाध्यक्ष भरत पटेल के आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन तथा जिलाध्यक्ष विश्वासराज शुक्ला द्वारा प्रदत्त संगठनात्मक अधिकारों के तहत ये नियुक्तियां की गई हैं। जारी जानकारी के अनुसार, शाला केकरपानी में पदस्थ संजय शुक्ला को जिला संगठन मंत्री सह मीडिया प्रभारी तथा शासकीय शाला बैलिया में पदस्थ राजेश जैन को जिला सह-सचिव के दायित्व पर मनोनीत किया गया है। दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को नई ऊर्जा देने, शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने तथा जिले के शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को संगठन के मंच तक पहुंचाने की अपेक्षा जताई गई है। संगठन की मजबूती, आपसी समन्वय और शिक्षकों के अधिकारों के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर भी जोर दिया गया है। नियुक्तियों पर संगठन की ओर से दोनों पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की गई। संघ ने विश्वास जताया कि दोनों पदाधिकारी अपनी सक्रियता, कर्तव्यनिष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण से शिक्षक हितों की रक्षा तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने एकता, संघर्ष, सम्मान और शिक्षक हितों को अपना मूल संकल्प बताते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया है।

विधायक, कमिश्नर और कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

ग्राम सरई में जन विश्वास शिविर, 124 आवेदन मिले

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।



जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत सरई में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं। इस दौरान लगभग 124 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवेदनों की जांच कर नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। शिविर में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता, कलेक्टर रत्नाकर झा और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने कहा कि प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करें और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का विधायक, कमिश्नर और कलेक्टर ने निरीक्षण किया। राजस्व, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, खाद्य, नगरीय प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, उनकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी ग्रामीणों को दी। स्टॉलों के माध्यम से नागरिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। आशा देवी, पुष्पा सिंह और सुनीता नायक ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिले के आठ स्व-सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियों के लिए कुल 45 लाख 50 हजार रुपये के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इस राशि से संबंधित समूहों की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शिविर में वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकटराव चनाप, पुष्पराजगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसीम अहमद भट्ट, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिश्चंद्र द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

केवई नदी में 18 दिन में दो की डूबने से मौत

20 सितंबर को 15 वर्षीय किशोर ने गंवाई जान, 8 अक्टूबर को 65 वर्षीय वृद्ध की मौत

एक ही स्थान पर दो घटनाओं से लोगों में दहशत

हरिभूमि न्यूज कोतमा।



कोतमा क्षेत्र की केवई नदी में महज 18 दिनों के भीतर डूबने से दो लोगों की मौत ने नदी में आवाजाही की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 20 सितंबर को इसी स्थान पर 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हुई थी। इसके बाद 8 अक्टूबर को 65 वर्षीय वृद्ध मोट्टन सिंह गोंड भी गहरे पानी में डूब गए। एक ही स्थान के आसपास हुई इन दो घटनाओं के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। लगातार हो रही मौतों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या नदी पार करने के जोखिम को लेकर लोगों को पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है और खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं या नहीं। जानकारी के अनुसार, डराईबहरा निवासी मोट्टन सिंह गोंड, थाना भालूमाड़ा क्षेत्र, 8 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे अपने घर से लहसुई गांव जाने के लिए निकले थे। रास्ते में केवई नदी पार करने के लिए उन्होंने अपने कपड़े और जूते उतारकर झोले में रख दिए और नदी में उतर गए। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से वृद्ध के शव को नदी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। केवई नदी के इसी स्थान पर 20 सितंबर को कोतमा निवासी 15 वर्षीय किशोर की भी गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। पहली घटना के महज 18 दिन बाद दूसरी मौत ने नदी में उतरने और उसे पार करने के दौरान होने वाले खतरे को फिर सामने ला दिया है। लगातार दो लोगों की जान जाने के बाद नदी के खतरनाक हिस्सों की पहचान, लोगों को चेतावनी देने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि किसी स्थान पर गहराई अधिक है और वहां से लोगों की नियमित आवाजाही होती है, तो ऐसे स्थानों पर चेतावनी संकेत और जन-जागरूकता जैसे उपाय दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मददगार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित प्रशासन नदी के ऐसे जोखिम वाले स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह के दुख का सामना न करना पड़े।

कमिश्नर-कलेक्टर ने आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खमरौध का किया निरीक्षण



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता एवं अनूपपुर कलेक्टर रत्नाकर झा ने शुक्रवार को पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खमरौध का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्ड के संधारण और उसमें दर्ज जानकारियों को अद्यतन रखने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र में उपस्थित एक गर्भवती महिला से सीधे बातचीत कर उसके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलका तिवारी से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ समय पर आवश्यक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच और जरूरत के अनुसार आगे की निगरानी भी की जाए, ताकि गर्भावस्था के दौरान किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर समय रहते ध्यान दिया जा सके। कमिश्नर ने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करने तथा उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध अन्य सेवाओं और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी, पुष्पराजगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसीम अहमद भट्ट सहित संबंधित अधिकारी एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

वनांचल के 162 से अधिक युवाओं ने रोजगार मेले में लिया भाग

जैतहरी में सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की दी गई जानकारी



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। वनांचल के बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत वन डिपो जैतहरी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत आयोजित इस मेले में जैतहरी तहसील के विभिन्न ग्रामों से आए 162 से अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। वनमंडलाधिकारी अनूपपुर के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के अवसरों से अवगत कराया गया। इस दौरान एल एंड टी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग सेंटर, वन विद्यालय लखनादौन, जिला सिवनी के केंद्र प्रभारी कमल चन्द्रवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को एल एंड टी द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण में प्रवेश की प्रक्रिया, प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले अवसरों और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वन परिक्षेत्राधिकारी जैतहरी विवेक मिश्रा और उप वनक्षेत्रपाल रिचर्ड रेगी राव सहित वन परिक्षेत्र जैतहरी के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। वन विभाग के कर्मचारियों ने आयोजन की व्यवस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मेले तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग दिया। वनांचल के 162 से अधिक युवाओं की सहभागिता के साथ आयोजित इस रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं से परिचित कराया गया। अब प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं को इन अवसरों से जोड़कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।

डिवाइडर नहीं, तो सड़क पर मौत का खतरा बरकरार

बदरा में मवेशी से टकराई बाइक, तीन लोग घायल, गाय की मौत

हरिभूमि न्यूज बदरा। कोतमा मार्ग पर बदरा बस स्टैंड के आगे शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मवेशी के कारण सड़क हादसा हो गया। कोतमा की ओर से आ रही बाइक पर सवार दो पुरुष और एक महिला मवेशी की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार पुरुषों के हाथ-पैर में चोटें आईं, जबकि महिला भी घायल हुई है।

इस दुर्घटना ने एक बार फिर बदरा के जमुना गेट से श्रमिक नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस हिस्से में डिवाइडर नहीं होने और सड़क पर मवेशियों की आवाजाही के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जमुना गेट से श्रमिक नगर तक सड़क के दोनों ओर आवासीय मकान और दुकानें बनी हुई हैं। इसके कारण सुबह से शाम तक इस मार्ग पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। दोपहिया वाहनों के साथ चारपहिया और भारी वाहन भी तेज रफ्तार से गुजरते हैं। ऐसे में अचानक सड़क पर मवेशी आ जाने से वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता और हादसे हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर डिवाइडर का अभाव और मवेशियों का खुलेआम सड़क पर घूमना दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहां हर महीने कई मवेशियों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। हालांकि, इन घटनाओं का आधिकारिक आंकड़ा सामने आना बाकी है।

सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को लेकर स्थानीय लोगों ने उनके मालिकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कुछ पशुपालक अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वे मुख्य मार्ग तक पहुंच जाते हैं। इससे न केवल मवेशियों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि वाहन चालकों और राहगीरों को भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। बदरा के इस व्यस्त मार्ग पर लगातार दुर्घटनाओं की आशंका के बीच सवाल है कि सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विभाग अब तक प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा पाए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि जमुना गेट से श्रमिक नगर तक सड़क की स्थिति का निरीक्षण कर डिवाइडर सहित आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। साथ ही सड़क पर खुले घूमने वाले मवेशियों को नियंत्रित करने और उनके मालिकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।